### AAE-4(H)

# सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

# अक्तूबर, 2011

## संसदीय वित्तीय नियंत्रण तथा सरकारी बजट प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंकं : 65

## अनुमत पुस्तकें :

भारत का संविधान 1.

सामान्य वित्तीय नियमावली-2005

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978

लोक सभा के कार्य संचालन संबंधी नियमावली एवं प्रक्रियाएं - नवां संस्करण

एफआरबीएम अधिनियम और एफआरबीएम नियमावली-2004

भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम एवं नियमावली

### टिप्पणियां :

(1) इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न और 2 पृष्ठ हैं।

(2) कुल छह प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीन प्रश्नों के उत्तर भाग 'क' से और तीन प्रश्नों के उत्तर भाग 'ख' से दीजिए।

(3) प्रश्न संख्या 5 जोकि 15 अंक का है, अनिवार्य है।

(4) अन्य सभी प्रश्नों के अंक समान (10) हैं।

(5) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर दें और संविधान के संबंधित प्रावधानों एवं अन्य नियमों (जहां लागू हो) का उल्लेख करें।

### भाग 'क'

- 1. संसद की रचना का वर्णन कीजिए? संसद के सदनों की अवधि से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
- 2. कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? धन विधेयक के संबंध में संविधान में दी गई विशेष प्रक्रियाएं क्या हैं?

3. (i) संसद की कार्यवाही को क्या संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? (5 अंक)

(ii) राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। (5 अंक)

4. जब भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा करता है तो संघ सरकार की शक्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? (10 अंक)

#### भाग 'ख'

5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएः

(क) अनुदानों की ब्योरेवार मांग (3 अंक)

(ख) आउटकम बजट (3 अंक)

(ग) विनियोग विधेयक (3 अंक)

(घ) सांकेतिक पूरक अनुदान (3 अंक)

(ङ) वार्षिक वित्तीय विवरण (3 अंक)

6. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विवरणों के महत्व का वर्णन कीजिए। (10 अंक)

- 7. "भुगतान और लेखा कार्यालय महत्वपूर्ण बजटीय नियंत्रण कार्य करता है।" व्याख्या कीजिए। (10 अंक)
- 8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों के बारे में बकाया कर्जों को इक्विटी निवेश अथवा सहायता अनुदान में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

  (10 अंक)

#### AAE-4(E)

### ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

#### OCTOBER, 2011

# PARLIAMENTARY FINANCIAL CONTROL AND GOVERNMENT BUDGETING

(With Books)

Time Allowed: 2 Hours

Maximum Marks: 65

#### Books allowed:

- 1. Constitution of India.
- 2. General Financial Rules 2005.
- 3. Delegation of Financial Power Rules, 1978.
- 4. Rules and Procedures of Conduct of Business in Lok Sabha-Ninth Edition.
- 5. FRBM Act and FRBM Rules 2004.
- 6. Contingency Fund of India Act & Rules.
- Note: 1. The question paper consists of 8 questions and has 2 pages.
  - 2. Attempt six questions. Three from Part 'A' and three from Part 'B'.
  - 3. Question number 5 carrying 15 marks is compulsory.
  - 4. All other questions carry equal (10) marks.
  - The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to the relevant provisions of the Constitution of India or other rules (wherever applicable).

#### PART'A'

1. What is the composition of the Parliament? Delineate the constitutional provisions with regard to the duration of the Houses of Parliament.

(10 marks)

2. Who is the final authority to decide whether a Bill is a Money Bill or not? What are the special procedures provided for in the Constitution in respect of Money Bills? (10 marks)

3. (i) What constitutional protection has been accorded to the proceedings of Parliament? (5 marks)

(ii) Delineate the legislative powers of the President.

4. When the President of India proclaims emergency under Article 352 of the Constitution, what effect does it have on the power of the Union Government?

#### PART 'B'

5. Briefly explain the following:

(3 marks) (a) Detailed Demand for Grants

(3 marks) (b) Outcome Budget

(3 marks) (c) Appropriation Bill

(3 marks) (d) Token Supplementary Grants

(3 marks) (e) Annual Financial Statement

6. Describe the importance of the different Statements laid before Parliament as required under the FRBM Act, 2003. (10 marks)

- "The Pay & Accounts Office performs important budgetary control functions." Explain.
- 8. Delineate the provisions for conversion of outstanding loans into equity investments or grant-in-aid in respect of Public Sector Enterprises/ Undertakings.